



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275129
CG-DL-E-03082026-275129

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4131]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4131]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4307(अ).— जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कतिपय निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या न्यासों या आयोगों की विनिर्दिष्ट आय की छूट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसकी उप-धारा (4) के अधीन, निम्न पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यथा:-

- (i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पिछला प्रचालन और इसके अंतर्गत जारी कोई आदेश या विधित किया गया कोई कार्य या हुई बात
- (ii) 1961 के अधिनियम या इस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित या किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तिथि को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और (1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही (नोटिस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) पर लागू रहेंगे और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम कि विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

और जहाँ कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ड) में यह प्रावधान है कि इसके प्रारंभ होने की तारीख को किसी आयकर प्राधिकरण या निरसित आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई अन्य प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही को इस तरह से जारी रखा जायेगा और उसका निपटान किया जायेगा जैसे कि इस अधिनियम को अधिनियमित ही न किया गया हो;

अतः अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ड) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई), पंचकूला (AAAGT0008A), जो कि हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2008 (2008 का अधिनियम सं. 19), के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) केन्द्र सरकार और हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, असाइनमेंट तथा अंशदान और ऋण;
- (ख) शुल्क, जैसे संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रवासन शुल्क, प्रतिलेखन शुल्क, आदि;
- (ग) दंड सहित रॉयल्टी और प्रभार;
- (घ) वसीयत, दान और बंदोबस्ती या अन्य योगदान;
- (ङ) हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड में निहित किसी प्रतिभूतियों और किराए की बिक्री आय और संपत्ति से लाभ; तथा
- (च) बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई), पंचकूला:-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) इसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) 1961 के अधिनियम की धारा 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष, 2023-24 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए लागू मानी जाएगी.

[अधिसूचना सं. 103/2026/फा. सं. 300196/76/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण- ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर किए गए आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2026

S.O. 4307(E).— Whereas, section 10 (46) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of specified income of certain bodies or authorities or Boards or Trusts or Commissions as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that section;

And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536 (1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);

And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), *inter alia*, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-

- (i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or
- (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;

And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1st April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;

And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the repealed Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2) (a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies, for the purposes of section 10 (46) of the Act of 1961, 'Haryana State Board of Technical Education (HSBTE), Panchkula' (PAN: AAAGT0008A), a Board constituted by the State Government of Haryana under the Haryana Board of Technical Education Act, 2008 (Act No. 19 of 2008), in respect of the following specified income arising to the said board namely :-

- (a) Grants, Assignments and Contributions and loans received from the Central Government and the State Government of Haryana;
- (b) Fees, such as Affiliation Fees, Examination Fees, Migration Fees, Transcription Fees, etc.;
- (c) Royalties and charges including penalties;
- (d) Bequests, donations and endowments or other contributions;
- (e) Sale proceeds of any securities and Rents and profits from property vested in Haryana State Board of Technical Education; and
- (f) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Haryana State Board of Technical Education (HSBTE), Panchkula –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provisions of section 139(4C) (g) of the Act of 1961.

3. Failure to comply with these conditions shall result in the initiation of penal actions under the provisions of the Act of 1961, and withdrawal of exemption granted under section 10(46) of the Act of 1961.

4. This notification shall be deemed to have been applied for assessment year 2024-25 relevant for the financial year 2023-24.

[Notification No. 103/2026/F. No.300196/76/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that the interests of no person are being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application filed before the Board or Income-tax Department] to this notification.